



2025:AHC: 9940

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट सी संख्या - 38368 वर्ष 2025

चेतराम

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता

: संजय कुमार मिश्रा, श्रवण कुमार पांडेय

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता

: मुख्य स्थायी अधिवक्ता, राकेश कुमार श्रीवास्तव,
सुनील कुमार सिंह

न्यायालय संख्या-35

प्रकाशनार्थ स्वीकृत

माननीय न्यायमूर्ति डॉ. योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री श्रवण कुमार पांडे और राज्य-प्रत्यर्थियों के लिए विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री ओ.पी. शर्मा के साथ उपस्थित विद्वान मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री जे.एन. मोर्य को सुना।

2. भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत वर्तमान रिट याचिका उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अंतर्गत कार्यवाहियों से उद्भूत वाद संख्या 14775 वर्ष 2023 (कंप्यूटर वाद संख्या टी202311270214775), भूमि प्रबंधक समिति बनाम चेताराम में प्रत्यर्थी संख्या 4, अर्थात् तहसीलदार (न्यायिक)/सहायक कलेक्टर, तहसील दादरी, जिला गौतम बुद्ध नगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.03.2025 के साथ-साथ प्रत्यर्थी संख्या 2, अपर आयुक्त (प्रशासन)- III, मेरठ मंडल, मेरठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.08.2025 को रद्द करने के लिए संस्थित की गई है, जिसके द्वारा संहिता की धारा 210 के अंतर्गत याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षण को खारिज कर दिया गया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. यद्यपि आक्षेपित आदेश प्रकृति में अंतर्वर्ती हैं, रिट याचिका संहिता, 2006 की धारा 67 के अंतर्गत संक्षिप्त कार्यवाहियों में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश VII नियम 11 की प्रयोज्यता से संबंधित विधि का एक सारवान और आवर्ती प्रश्न उठाती है। यह प्रश्न महत्व प्राप्त करता है, क्योंकि धारा 67 के अंतर्गत कार्यवाहियों का उद्देश्य एक त्वरित उपचार प्रदान करना है, जबकि आदेश VII नियम 11 के अंतर्गत वादपत्र को अस्वीकृत करने की शक्ति शुरुआत में ही उन कार्यवाहियों को समाप्त करने के लिए संचालित होती है, जो विधि द्वारा वर्जित हैं या जो वाद हेतुक का खुलासा नहीं करती हैं। यह मुद्दा राजस्व न्यायालयों के समक्ष बार-बार उठा है और इसलिए, विधिक स्थिति की एक सुविचारित व्याख्या का आह्वान करता है।

4. याचिकाकर्ता के विरुद्ध ग्राम सभा की भूमि पर अनधिकृत कब्जे के अभिकथन पर संहिता, 2006 की धारा 67 (1) के अंतर्गत कार्यवाहियां शुरू की गई थीं। कार्यवाहियों की शुरुआत संबंधित राजस्व प्राधिकारी द्वारा निर्धारित तरीके से प्रस्तुत की गई जानकारी पर आधारित थी, जिसका समापन धारा 67(1) के अंतर्गत परिकल्पित आर.सी. प्रपत्र-19 में प्रस्तुत एक रिपोर्ट में हुआ। इसके परिणामस्वरूप, धारा 67(2) के अंतर्गत याचिकाकर्ता को आर.सी. प्रपत्र-20 में एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिसमें उसे निर्धारित समय के भीतर आपत्तियां प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया।

5. धारा 67(2) के अंतर्गत जारी नोटिस प्राप्त होने पर, याचिकाकर्ता ने, उसके अंतर्गत परिकल्पित आपत्तियों तक खुद को सीमित रखने के बजाय, सी.पी.सी. के आदेश VII नियम 11 के अंतर्गत शीर्षक वाला एक आवेदन दाखिल किया, जिसमें कथित अपोषणीयता के आधार पर शुरुआत में ही कार्यवाहियों को खारिज करने की मांग की गई। तत्पश्चात, याचिकाकर्ता ने धारा 67(2) के अंतर्गत परिकल्पित 21.04.2024 को गुण-दोष के आधार पर विस्तृत आपत्तियां भी दाखिल कीं।

6. सहायक कलेक्टर ने आदेश दिनांक 24.03.2025 द्वारा, शुरुआत में ही सी.पी.सी. के आदेश VII नियम 11 के अंतर्गत आवेदन पर निर्णय लेने से इनकार कर दिया, यह अभिनिर्धारित करते हुए कि पोषणीयता के संबंध में आपत्ति पर धारा 67(3) के अंतर्गत अंतिम न्यायनिर्णयन के स्तर पर गुण-दोष के आधार पर आपत्तियों के साथ विचार किया जाए।

7. इससे व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने संहिता, 2006 की धारा 210 के अंतर्गत एक पुनरीक्षण प्रस्तुत किया, जिसे अपर आयुक्त द्वारा 19.08.2025 को खारिज कर दिया गया, यह अभिनिर्धारित करते हुए कि कोई क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि या अवैधता नहीं पाई गई।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



8. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने पुरजोर तर्क दिया कि सी.पी.सी. के आदेश VII नियम 11 के अंतर्गत आवेदन ने पोषणीयता का एक शुद्ध प्रश्न उठाया है, जिसे गुण-दोष के आधार पर न्यायनिर्णयन से पहले एक प्रारंभिक मुद्दे के रूप में तय किया जाना चाहिए था। संहिता, 2006 की धारा 214 पर भरोसा किया गया था, यह तर्क देते हुए कि सी.पी.सी. के सिद्धांत लागू होते हैं और ऐसे न्यायनिर्णयन को स्थगित करना क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि के समान है, जो अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हस्तक्षेप को अधिकृत करता है।

9. इसके विपरीत, राज्य-प्रत्यर्थियों के लिए उपस्थित विद्वान मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि धारा 67 के अंतर्गत कार्यवाहियां संक्षिप्त कार्यवाहियां हैं, जिन पर उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 186 के आधार पर सी.पी.सी. के प्रावधान सख्त अर्थों में लागू नहीं होते हैं। यह प्रस्तुत किया गया था कि आपतियों का एकीकृत न्यायनिर्णयन सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण को शीघ्र हटाने की वैधानिक योजना और विधायी आशय के अनुरूप है।

10. विचार के लिए उत्पन्न होने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश VII नियम 11 के प्रावधान, जो वादपत्र की नामंजूरी पर विचार करते हैं, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अंतर्गत शुरू की गई संक्षिप्त कार्यवाहियों पर लागू होते हैं, और यदि हां, तो क्या सहायक कलेक्टर के लिए ऐसी आपति को प्रारंभिक विवादक के रूप में न्यायनिर्णित करना आज्ञापक रूप से आवश्यक है?

11. विवाद को समझने के लिए, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के प्रासंगिक प्रावधान नीचे दिए गए हैं:

"धारा 67. ग्राम पंचायत की संपत्ति को नुकसान, दुर्विनियोग और सदोष कब्जे को रोकने की शक्ति।-(1) जहां इस संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकारी को सौंपी गई या सौंपी गई मानी जाने वाली किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है या दुर्विनियोग किया जाता है, या जहां कोई ग्राम पंचायत या अन्य प्राधिकारी इस संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत किसी भी भूमि का कब्जा लेने का हकदार है और ऐसी भूमि पर उक्त प्रावधानों के अनुसार अन्यथा कब्जा कर लिया जाता है, भूमि प्रबंधक समिति या अन्य प्राधिकारी या संबंधित लेखपाल, जैसी भी स्थिति हो, निर्धारित तरीके से संबंधित सहायक कलेक्टर को सूचित करेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(2) जहां उप-धारा (1) के अंतर्गत प्राप्त जानकारी से या अन्यथा, सहायक कलेक्टर संतुष्ट है कि उप-धारा (1) में निर्दिष्ट किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है या दुर्विनियोग किया गया है, या कोई व्यक्ति इस संहिता के प्रावधानों के उल्लंघन में उस उप-धारा में निर्दिष्ट किसी भूमि पर कब्जा किए हुए है, तो वह संबंधित व्यक्ति को कारण बताओ नोटिस जारी करेगा कि नोटिस में निर्दिष्ट राशि से अनधिक नुकसान, दुर्विनियोग या सदोष कब्जे के लिए मुआवजा उससे क्यों न वसूल किया जाए और उसे ऐसी भूमि से बेदखल क्यों न किया जाए।

(3) यदि वह व्यक्ति जिसे उप-धारा (2) के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया है, नोटिस में निर्दिष्ट समय के भीतर या ऐसे विस्तारित समय के भीतर, जो सहायक कलेक्टर इस संबंध में अनुमति दे सकता है, कारण बताने में विफल रहता है, या यदि बताया गया कारण अपर्याप्त पाया जाता है, तो सहायक कलेक्टर निर्देश दे सकता है कि ऐसे व्यक्ति को भूमि से बेदखल किया जाए, और उस उद्देश्य के लिए, ऐसे बल का उपयोग कर सकता है या करवा सकता है, जो आवश्यक हो, और निर्देश दे सकता है कि संपत्ति के नुकसान या दुर्विनियोग या सदोष कब्जे के लिए, जैसी भी स्थिति हो, मुआवजे की राशि ऐसे व्यक्ति से भू-राजस्व के बकाए के रूप में वसूल किया जाए।

(4) यदि सहायक कलेक्टर की राय है कि कारण बताने वाला व्यक्ति उप-धारा (2) के अंतर्गत नोटिस में निर्दिष्ट नुकसान या दुर्विनियोग या सदोष कब्जे का दोषी नहीं है, तो वह नोटिस का उन्मोचन करेगा।

(5) उप-धारा (3) या उप-धारा (4) के अंतर्गत सहायक कलेक्टर के आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति, ऐसे आदेश की तिथि से तीस दिनों के भीतर, कलेक्टर को अपील प्रस्तुत कर सकता है।

(6) इस संहिता के किसी अन्य प्रावधान में किसी बात के होते हुए भी और इस धारा के प्रावधानों के अधीन, इस धारा के अंतर्गत सहायक कलेक्टर का प्रत्येक आदेश, उप-धारा (5) के प्रावधानों के अधीन, अंतिम होगा।

(7) इस धारा के अंतर्गत की गई किसी भी कार्रवाई में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया वैसी होगी जैसी निर्धारित की जाए।

स्पष्टीकरण - इस धारा के प्रयोजनों के लिए, शब्द 'भूमि' में उस पर खड़े पेड़ और भवन शामिल होंगे।"

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



"धारा 214. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 और परिसीमा अधिनियम, 1963 की प्रयोज्यता - जब तक कि इस संहिता द्वारा या इसके अंतर्गत स्पष्ट रूप से अन्यथा प्रावधान न किया गया हो, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 और परिसीमा अधिनियम, 1963 के प्रावधान इस संहिता के अंतर्गत प्रत्येक वाद, आवेदन या कार्यवाहियों पर लागू होंगे।"

"नियम 186. सी.पी.सी. का लागू न होना (धारा 214) - सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के प्रावधान संहिता या इन नियमों के अंतर्गत संक्षिप्त कार्यवाहियों पर लागू नहीं होंगे, लेकिन सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में निहित सिद्धांतों और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन ऐसी कार्यवाहियों के निस्तारण में किया जाएगा।"

12. उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 राजस्व अधिकारियों को ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकारी को सौंपी गई या सौंपी गई मानी जाने वाली संपत्ति के नुकसान, दुर्विनियोग और सदोष कब्जे को रोकने की शक्ति प्रदान करती है। उप-धारा (1) भूमि प्रबंधक समिति, संबंधित स्थानीय प्राधिकारी या लेखपाल, जैसी भी स्थिति हो, को ऐसी भूमि के नुकसान, दुर्विनियोग या अनधिकृत कब्जे पर निर्धारित तरीके से सहायक कलेक्टर को सूचित करने के लिए बाध्य करती है। उप-धारा (2) सहायक कलेक्टर को, ऐसी जानकारी प्राप्त होने पर या अन्यथा, और नुकसान, दुर्विनियोग या अनधिकृत कब्जे के अस्तित्व से संतुष्ट होने पर, एक कारण बताओ नोटिस जारी करने का अधिकार देती है, जिसमें संबंधित व्यक्ति से यह स्पष्ट करने के लिए कहा जाता है कि मुआवजा क्यों नहीं वसूला जाना चाहिए और बेदखली का आदेश क्यों नहीं दिया जाना चाहिए। उप-धारा (3) और (4) सहायक कलेक्टर को कारण बताने में विफलता या उसकी अपर्याप्तता पर बेदखली और भू-राजस्व के बकाए के रूप में मुआवजे की वसूली का आदेश देने या विकल्प के रूप में, यदि कोई उल्लंघन नहीं पाया जाता है तो नोटिस को उन्मोचित करने का अधिकार प्रदान करती है। उप-धारा (5) तीस दिनों के भीतर कलेक्टर के समक्ष एक वैधानिक अपील प्रदान करती है। उप-धारा (6) अपीलीय उपचार के अधीन, धारा के अंतर्गत पारित आदेशों को अंतिम रूप प्रदान करती है। उप-धारा (7) यह आज्ञापक करती है कि अपनाई जाने वाली प्रक्रिया वैसी होगी जैसी निर्धारित की जाए।

13. संहिता के अंतर्गत कार्यवाहियों में सिविल प्रक्रिया संहिता की प्रयोज्यता संहिता, 2006 की धारा 214 द्वारा शासित होती है, जो सी.पी.सी. को तब तक लागू करती है जब तक कि स्पष्ट रूप से अन्यथा प्रावधान न किया गया हो। ऐसा स्पष्ट अपवर्जन उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



नियमावली, 2016 के नियम 186 में निहित है, जो स्पष्ट रूप से प्रावधान करता है कि सी.पी.सी. के प्रावधान संक्षिप्त कार्यवाहियों पर लागू नहीं होंगे, हालांकि इसके सिद्धांतों और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया जाएगा।

14. धारा 67, धारा 214 और नियम 186 का संयुक्त पठन वैधानिक स्थिति को स्पष्ट करता है। धारा 67 ग्राम सभा और सार्वजनिक भूमि की सुरक्षा के लिए एक संक्षिप्त तंत्र बनाती है, जो सहायक कलेक्टर को सिविल मुकदमेबाजी का सहारा लिए बिना जानकारी या आधिकारिक रिपोर्ट पर कार्रवाई करने का अधिकार देती है। कार्यवाहियों को त्वरित, निवारक और उपचारात्मक होने के लिए डिज़ाइन किया गया है। जबकि धारा 214 आम तौर पर सी.पी.सी. प्रावधानों को लागू करने का प्रावधान करती है, यह स्पष्ट अपवर्जन के अधीन ऐसा करती है। नियम 186 ऐसा ही एक स्पष्ट अपवर्जन है। यह स्पष्ट रूप से सी.पी.सी. प्रावधानों को संक्षिप्त कार्यवाहियों पर लागू होने से रोकता है, जबकि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के साथ-साथ केवल उनके मार्गदर्शक सिद्धांतों को संरक्षित करता है। इस प्रकार, वैधानिक योजना सचेत रूप से प्रशासनिक दक्षता के साथ प्रक्रियात्मक निष्पक्षता को संतुलित करती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि सिविल प्रक्रिया की कठोरता ग्राम पंचायत संपत्ति पर सदोष कब्जे में पाए गए व्यक्तियों की त्वरित बेदखली के विधायी उद्देश्य में बाधा न डाले।

15. उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अंतर्गत कार्यवाहियां प्रशासनिक-सह-अर्ध-न्यायिक संक्षिप्त कार्यवाहियां हैं और सिविल वाद का गठन नहीं करती हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत एक सिविल वाद सी.पी.सी. के आदेश IV नियम 1 के अंतर्गत एक वादपत्र की प्रस्तुति के साथ शुरू होता है, जिसके बाद समन की तामीली, विवाद्यों को विरचित करना, साक्ष्य दर्ज करना और एक पूर्ण विचारण के माध्यम से न्यायनिर्णयन होता है।

16. इसके बिल्कुल विपरीत, धारा 67 के अंतर्गत कार्यवाहियां किसी वाद-पत्र से उत्पन्न नहीं होती हैं, बल्कि भूमि प्रबंधक समिति, संबंधित स्थानीय प्राधिकारी या लेखपाल द्वारा उप-धारा (1) के अनुसार प्रस्तुत की गई जानकारी पर शुरू होती हैं, या जहां सहायक कलेक्टर, उप-धारा (2) के अंतर्गत ऐसी जानकारी या अन्यथा, ग्राम पंचायत में निहित भूमि के नुकसान, दुर्विनियोग या अनधिकृत कब्जे के संबंध में संतुष्ट है।

17. उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अंतर्गत प्रक्रियात्मक प्रक्षेप-वक्र ग्राम सभा की भूमि पर कथित अनधिकृत कब्जे के संबंध में जानकारी या आधिकारिक रिपोर्ट प्राप्त होने के

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



साथ शुरू होता है, जिस पर संबंधित व्यक्ति को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है, जिसे उसके बाद आपतियां दाखिल करने का अवसर प्रदान किया जाता है, जिसके बाद प्राधिकारी द्वारा उचित समझे जाने पर एक संक्षिप्त जांच की जाती है, जिसका समापन विधि के अनुसार एक सकारण अंतिम आदेश पारित करने में होता है।

18. जहां कोई संविधि एक विशेष मंच बनाता है और एक विशिष्ट और स्वयंपूर्ण प्रक्रिया निर्धारित करता है, वहां साधारण सिविल न्यायालय की प्रक्रिया से ली गई अवधारणाओं और तकनीकी को ऐसी कार्यवाहियों में तब तक आयात नहीं किया जा सकता, जब तक कि संविधि स्वयं स्पष्ट रूप से ऐसा प्रावधान न करे। राजस्व बेदखली कार्यवाहियां, विशेष रूप से सार्वजनिक भूमि पर अनधिकृत कब्जे को हटाने से संबंधित कार्यवाहियां, लगातार प्रकृति में संक्षिप्त समझी गई हैं, जिनका उद्देश्य त्वरित और प्रभावी उपचार सुरक्षित करना है, और वे सिविल प्रक्रिया संहिता की तकनीकी कठोरता द्वारा शासित नहीं होती हैं।

19. उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 में निहित स्पष्ट विधायी उद्देश्य सार्वजनिक और ग्राम सभा की भूमि को शीघ्र खाली कराना है ताकि सार्वजनिक अनिष्ट को रोका जा सके और सामुदायिक संपत्ति की रक्षा की जा सके। सिविल मुकदमेबाजी की प्रक्रियात्मक बाधाओं की शुरुआत - जैसे विस्तृत अभिवचन, तकनीकी आपतियां और प्रतिवादात्मक मुकदमेबाजी के लिए बनाए गए प्रारंभिक आवेदन - इस उद्देश्य को विफल कर देंगे और वैधानिक तंत्र के संक्षिप्त चरित्र को कमजोर कर देंगे।

20. सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश VII नियम 11 न्यायालय को अन्य बातों के साथ-साथ इस आधार पर शुरुआत में ही वाद-पत्र को खारिज करने की शक्ति प्रदान करता है कि वह वाद हेतुक का खुलासा नहीं करता है या कि वादपत्र में निहित कथनों से प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है। यह प्रावधान इस कल्याणकारी सिद्धांत पर आधारित है कि तुच्छ, तंग करने वाली या विधिक रूप से असमर्थनीय मुकदमेबाजी को न्यायालय का समय बर्बाद करने या पक्षकारों को परिहार्य कार्यवाहियों के अधीन करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

21. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह प्रावधान अनिवार्य रूप से प्रक्रियात्मक, वाद-केंद्रित और शुरुआत-उन्मुख है। यह, सख्त अर्थों में, एक वाद-पत्र की प्रस्तुति द्वारा एक सिविल वाद के संस्थित होने की पूर्वकल्पना करता है और ऐसी प्रतिवादात्मक सिविल कार्यवाहियों की शुरुआत में

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



संचालित होने का उद्देश्य रखता है। इसलिए, इसकी वैचारिक नींव वाद-पत्र के अस्तित्व से अटूट रूप से जुड़ी हुई है, और यह एक साधारण सिविल वाद के ढांचे के बाहर स्वतः लागू नहीं होता है।

22. सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रक्रियात्मक प्रावधानों को विशेष संविधियों के अंतर्गत कार्यवाहियों पर यंत्रवत या स्वचालित रूप से लागू नहीं किया जाना चाहिए, विशेष रूप से जहां ऐसे संविधि एक विशिष्ट प्रक्रिया निर्धारित करते हैं और संहिता के अनुप्रयोग को स्पष्ट रूप से सीमित या अपवर्जित करते हैं। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 का नियम 186 स्पष्ट रूप से सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों को संक्षिप्त कार्यवाहियों पर लागू होने से बाहर रखता है, जबकि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के साथ केवल इसके मार्गदर्शक सिद्धांतों को संरक्षित करता है। सूत्र *एक्सप्रेसियो यूनियस एस्ट एक्सक्लूसियो अल्टेरियस* (एक की स्पष्ट अभिव्यक्ति दूसरे का अपवर्जन है) को लागू करते हुए, एक बार जब सी.पी.सी. के प्रावधानों को स्पष्ट रूप से बाहर कर दिया जाता है, तो धारा 214 के माध्यम से उनका अप्रत्यक्ष आयात अनुमेय नहीं है।

23. उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अंतर्गत कार्यवाहियां सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत समझे जाने वाले अर्थ में किसी वाद पत्र से उत्पन्न नहीं होती हैं। ऐसी कार्यवाहियों की शुरुआत आर.सी. प्रपत्र-19 रिपोर्ट पर आधारित होती है, जो एक वैधानिक कर्तव्य के निर्वहन में राजस्व कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत एक आधिकारिक रिपोर्ट है। ऐसी रिपोर्ट न तो कोई प्रतिवादात्मक अभिवचन है और न ही निजी अधिकारों का दावा करने वाला दावे का कथन है, बल्कि प्रशासनिक जानकारी का एक टुकड़ा मात्र है, जो सार्वजनिक भूमि पर कथित अनधिकृत कब्जे की जांच करने के सहायक कलेक्टर के वैधानिक दायित्व को गति प्रदान करता है।

24. इसलिए, आर.सी. प्रपत्र-19 रिपोर्ट को रूप, सार या विधिक चरित्र में वाद पत्र के समान नहीं माना जा सकता है। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश VII की कठोरता को आकर्षित करने के लिए इसे वाद पत्र के रूप में मानने का कोई भी प्रयास वैचारिक रूप से त्रुटिपूर्ण और विधिक रूप से असमर्थनीय होगा, और यह एक संक्षिप्त वैधानिक कार्यवाही में सिविल वाद न्यायशास्त्र को लागू करने के समान होगा, जहां विधायिका ने सचेत रूप से इसके अनुप्रयोग को बाहर रखा है।

25. ऐसी रिपोर्ट को वाद पत्र के समान मानना पूरी तरह से अनुचित होगा और एक मौलिक श्रेणी त्रुटि के समान होगा। वाद पत्र के अभाव में, आदेश VII नियम 11 का आह्वान करने का मूल आधार ही गायब है, जिससे उक्त प्रावधान संहिता की धारा 67 के अंतर्गत कार्यवाहियों पर पूरी

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



तरह से अनुपयुक्त हो जाता है। इसकी प्रयोज्यता का अपवर्जन उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 214 के साथ पठित नियम 186 द्वारा और भी पुष्ट हो जाता है।

26. वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध धारा 67 के अंतर्गत कार्यवाही की गई है, वह क्षेत्राधिकार, पोषणीयता या विधिक वर्जना के अस्तित्व से संबंधित आपतियां उठाने का हकदार है, जो धारा 67(2) के अंतर्गत परिकल्पित आपतियों का हिस्सा हैं। हालांकि, कानून यह आज्ञापक नहीं करता है कि ऐसी आपतियों को हमेशा अलग किया जाना चाहिए और प्रारंभिक विवादक के रूप में न्यायनिर्णित किया जाना चाहिए। यह निर्णय कि क्या प्रारंभिक आपति को अलग से लिया जाना चाहिए या गुण-दोष के साथ विचार किया जाना चाहिए, सक्षम प्राधिकारी के प्रक्रियात्मक विवेक के भीतर निहित है, जिसका प्रयोग आपति की प्रकृति और समग्र वैधानिक योजना को ध्यान में रखते हुए किया जाना है।

27. संक्षिप्त कार्यवाहियों में, प्रारंभिक आपतियों के पृथक न्यायनिर्णयन पर जोर देना अक्सर एक विलंबकारी युक्ति के रूप में कार्य करता है और त्वरित और प्रभावी उपचार प्रदान करने के मूल उद्देश्य को विफल करने की क्षमता रखता है। जब तक कि अभिलेख पर क्षेत्राधिकार संबंधी दोष स्पष्ट न हो और कार्यवाहियों की मूल जड़ तक न जाता हो, एकीकृत न्यायनिर्णयन अनुमेय और वांछनीय दोनों बना रहता है।

28. वर्तमान संदर्भ में, नैसर्गिक न्याय की आवश्यकताएं पूरी तरह से संतुष्ट हैं, क्योंकि याचिकाकर्ता को नोटिस तामील किया गया है, आपतियां दाखिल करने का अवसर प्रदान किया गया है, कार्यवाहियों में भाग लेने की अनुमति दी गई है, और उसने पुनरीक्षण के उपचार का लाभ उठाया है। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत खंडित या टुकड़ों में सुनवाई को आज्ञापक नहीं करते हैं, न ही वे प्रारंभिक स्तर पर अलग से हर आपति को न्यायनिर्णित करने की अपेक्षा करते हैं।

29. आदेश दिनांक 24.03.2025 प्रकृति में विशुद्ध रूप से प्रक्रियात्मक और अंतर्वर्ती है, जो केवल पोषणीयता के संबंध में आपतियों पर विचार को अंतिम न्यायनिर्णयन के स्तर तक स्थगित करता है। यह पक्षकारों के किसी भी मूल अधिकार का निर्णय नहीं करता है।

30. धारा 67 की उप-धारा (6) के अंतर्गत अंतिम रूप की विधायी घोषणा, जो केवल वैधानिक अपील के अधीन है, प्रक्रियात्मक बाधाओं को प्रतिबंधित करने के विधायी आशय को और रेखांकित

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



करती है और संक्षिप्त कार्यवाहियों में अंतर्वर्ती प्रक्रियात्मक आदेशों में हस्तक्षेप के विरुद्ध न्यायिक संयम को पुष्ट करती है।

31. यह भली-भांति स्थापित है कि संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत असाधारण क्षेत्राधिकार का प्रयोग संक्षिप्त कार्यवाहियों के दौरान पारित अंतर्वर्ती या प्रक्रियात्मक आदेशों के विरुद्ध नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि ऐसे आदेश क्षेत्राधिकार के स्पष्ट अभाव का खुलासा न करें या स्पष्ट अन्याय का परिणाम न हों।

32. उपरोक्त चर्चा के दृष्टिगत, इस न्यायालय का सुविचारित मत है कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का आदेश VII नियम 11, वाद पत्र-केंद्रित और वाद-उन्मुख होने के कारण, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अंतर्गत संक्षिप्त कार्यवाहियों पर स्वतः लागू नहीं होता है, जो वादपत्र की प्रस्तुति द्वारा संस्थित नहीं की जाती हैं, बल्कि आर.सी. प्रपत्र-19 रिपोर्ट द्वारा गति में लाई जाती हैं। परिणामस्वरूप, सी.पी.सी. के आदेश VII नियम 11 का आह्वान करके ऐसी कार्यवाहियों को खारिज करने की मांग करने वाला आवेदन, अपने सख्त अर्थों में, पोषणीय नहीं होगा।

33. साथ ही, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि राजस्व न्यायालयों को शुरुआत में ही यह जांचने के अधिकार से वंचित नहीं किया गया है कि क्या कार्यवाहियों की शुरुआत ही पूरी तरह से क्षेत्राधिकार के बिना है, विधि द्वारा वर्जित है, या वैधानिक प्रक्रिया के दुरुपयोग का गठन करती है। हालांकि सी.पी.सी. के आदेश VII नियम 11 के औपचारिक तंत्र को धारा 67 की कार्यवाहियों में आयात नहीं किया जा सकता है, अंतर्निहित सिद्धांत कि विधिक रूप से असमर्थनीय कार्यवाहियों को जारी रखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, एक उपयुक्त वाद में, संहिता की संक्षिप्त योजना और विधायी आशय के अनुरूप, सीमित तरीके से लागू किया जा सकता है।

34. पूर्वगामी चर्चा से जो विधिक स्थिति उभरती है उसे इस प्रकार संक्षेपित किया जा सकता है:

34.1 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अंतर्गत शुरू की गई कार्यवाहियां संक्षिप्त चरित्र की हैं, प्रकृति में प्रशासनिक-सह-अर्ध-न्यायिक हैं, और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 द्वारा शासित सिविल वादों का चरित्र ग्रहण नहीं करती हैं।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



34.2 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश VII नियम 11 के प्रावधान, जो वाद पत्र की अस्वीकृति पर विचार करते हैं, धारा 67 के अंतर्गत कार्यवाहियों पर पूरी तरह से अनुपयुक्त हैं, क्योंकि ऐसी कार्यवाहियां किसी भी वाद पत्र से उत्पन्न नहीं होती हैं।

34.3 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 का नियम 186 संहिता के अंतर्गत संक्षिप्त कार्यवाहियों में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अनुप्रयोग को स्पष्ट रूप से सिवाय इसके अंतर्निहित सिद्धांतों और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के पालन के बाहर रखता है।

34.4 वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध धारा 67 के अंतर्गत कार्यवाहियां शुरू की गई हैं, वह पोषणीयता, क्षेत्राधिकार, या किसी वैधानिक या विधिक वर्जना के अस्तित्व से संबंधित आपत्तियां उठाने का हकदार है; हालांकि, ऐसे व्यक्ति को यह मांग करने का कोई निहित, पूर्ण, या अजेय अधिकार प्राप्त नहीं होता है कि उन आपत्तियों को कार्यवाहियों के गुण-दोष पर विचार करने से अलग करके, स्वतंत्र प्रारंभिक विवादक के रूप में लिया जाए और न्यायनिर्णित किया जाए।

34.5 पोषणीयता से संबंधित आपत्तियां संहिता की धारा 67(2) के अंतर्गत परिकल्पित आपत्तियों का एक अभिन्न अंग हैं और साधारणतया वाद के गुण-दोष से अलग करके नहीं, बल्कि उनके साथ विचार किया जाना आवश्यक है।

34.6 प्रारंभिक आपत्तियों का पृथक या प्रारंभिक न्यायनिर्णयन केवल उन असाधारण स्थितियों में किया जाता है, जहां अभिलेख एक स्पष्ट और प्रत्यक्ष क्षेत्राधिकार संबंधी दोष दिखाई देता है।

34.7 धारा 67 के अंतर्गत संक्षिप्त कार्यवाहियों के दौरान पारित अंतर्वर्ती या प्रक्रियात्मक आदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट क्षेत्राधिकार के प्रयोग में हस्तक्षेप के अधीन नहीं हैं, जब तक कि ऐसे आदेश क्षेत्राधिकार के स्पष्ट अभाव का खुलासा न करें या स्पष्ट अन्याय का परिणाम न हों।

35. आक्षेपित आदेशों में कोई क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि, अवैधता या प्रक्रियात्मक अनुचितता प्रकट नहीं होती है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत अपने असाधारण क्षेत्राधिकार के प्रयोग में इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप को आवश्यक करे। इसलिए, रिट याचिका को गुण-दोष रहित माना जाता है और तदनुसार इसे **खारिज** किया जाता है।

36. हालांकि, न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, प्रत्यर्थी संख्या 4- तहसीलदार (न्यायिक)/सहायक कलेक्टर, तहसील दादरी, गौतम बुद्ध नगर को निर्देश दिया जाता है कि वे इस आदेश की प्रमाणित

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से आठ सप्ताह की अवधि के भीतर पोषणीयता से संबंधित आपत्तियों सहित सभी आपत्तियों पर विचार करते हुए सकारण और स्पष्ट अंतिम आदेश पारित करके वाद संख्या 14775 वर्ष 2023 के न्यायनिर्णयन को शीघ्र पूरा करें।

(न्यायमूर्ति डॉ. योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव)

14 जनवरी, 2026

शाहरोज/आर.के.के./-

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।